उत्तराखण्ड शासन वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनु०–७ संख्या: **८५५/ xxvii**(७) / 2011 देहरादून, दिनांक: **२** मार्च,2011

## कार्यालय ज्ञाप

विषय:—दिनांक 01—01—2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण को निरस्त किया जाना।

उपर्युक्त विषयक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में शासनादेश संख्याः 395/xxvii(7)/2010 दिनांक:17 अक्टूबर,2008 के कम में दिनांक 01—01—2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डो में वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनांकः 13 फरवरी,2009 ही निर्गत किया गया, परन्तु इसमें वेतन निर्धारण की कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं हो पाया है।

उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:598/xxvii (7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 द्वारा दिनांक 01—01—2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित निर्गत शासनादेश संख्या:395/xxvii (7)/2010 दिनांक: 17 अक्टूबर,2008 को आधार मानते हुए कट ऑफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुए इस तिथि के पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण संबंधित शासनादेश संख्याः 41/xxvii (7)/2010 दिनांक: 13 फरवरी,2009 की निहित व्यवस्थानुसार किया जाएगा तथा इस तिथि के बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों का संशोधित वेतन ढाँचे में प्रविष्टि वेतन का निर्धारण संगत वेतन बैण्ड के न्यूनतम में ग्रेड वेतन को जोड़ते हुए निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार के गजट दिनांक 29 अगस्त,2008 में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके बाद नये रिकूटों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधन वेतन ढांचे में निर्धारण इन नियमों की प्रथम सूची का भाग "क" का खण्ड—II वेतन बैण्ड में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा तथा दिनांक 01-01-2006 से और अधिसूचना के जारी होने के तारीक के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा।

अतः उक्त के संबंध में विभिन्न कर्मचारियों संघो द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2006 अथवा शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 जारी होने की तिथि के बीच नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या:598/xxvii(7)/2010 दिनांक 20 जुलाई,2010 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या:41/xxvii(7)/2010 दिनांक: 13 फरवरी,2009 में उल्लिखित वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारण किया जाए।

..पा रसूर सचिव संख्या : **854** (1) / XXVII(7) / 2011 तददिनांक प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून!
- 6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
- 7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
- 9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10.वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
- 11.समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
- 12.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 13.इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 14.निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 15.गार्ड फाइल ।

आज्ञा से ्रिक्ट (शरद चन्द्र पाण्डेय) अपर सचिव ।